(b) Government had already set up the National Handloom Development Corporation (NHDC) for making available yarn, dyes and other raw materials to handloom weavers at reasonble prices. A scheme for supply of hank yarn to handloom/weavers at mill-rate prices is also being implemented through NHDC. Under this scheme Government reimburses NHDC a subsidy @ 2 per cent of the value of yarn supplied towards cost of transportation and overheads.

(c) and (d) Do not arise.

सूती धागे का निर्यात

2435. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सूती धागे का निर्यात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर सूती धागे का निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या सूती धागे का निर्यात करने से पूर्व सरकार द्वारा भारतीय बुनकरों के लिये इसकी उपलब्धता संबंधी मामले पर विचार किया जाता है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सरकार सूती यार्न का निर्यात नहीं कर रही है । सरकार केवल अलग-अलग वर्ष के आधार पर सूती यार्न के निर्यात के लिये केवल मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा निर्धारित करती है ।

(ख) पिछले तीन केलेंडर वर्षों के दौरान सूती यार्न के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिये गये हैं:-

वर्ष	मात्रा मिलियन किग्रा० में	मूल्य मिलियन रु० में
1990	83.17	4757.99
1991	120.03	8540.03
1992	122.08	11043.62

(ग) सूती यार्न के निर्यात की उच्चतम सीमा की घोषणा अपरिष्कृत कपास के उत्पादन तथा देशीय मांग तथा सूती यार्न का उत्पादन तथा कीमतों, विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र के लिए यार्न की जरूरतों आदि जैसे सभी संबद्ध संघटकों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद की जाती है ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम, गुजरात द्वारा थोक विक्रेताओं को छूट दिया जाना

2436. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम, गुजरात अपने थोक विक्रेताओं को छूट देता है;

(ख) यदि हां, तो किन नियमों के अधीन यह छूट दी जाती है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक थोक विक्रेता को कितने-कितने प्रतिशत की कितनी-कितनी राशि की छूट दी गई;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी छूट दिये जाने में होने वाले कदाचारों के संबंध में अपने स्तर पर कोई जांच करवाई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) एन टी सी (धारक कम्पनी) द्वारा निर्धारित तथा एन टी सी (गुजरात) के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित बिक्री नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों और सामान्य वाणिज्यिक प्रक्रिया के अनुसार छूट दी जाती है ।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल बिक्री कारोबार में छूट का प्रतिशत निम्नोक्त अनुसार है:-

	प्र०श०
1989-90	1.39
1990-91	1.42
1991-92	1.88

पिछले 3 वर्षों के दौरान एन टी सी (गुजरात) द्वारा दी गई छूट की कुल मात्रा नीचे दी गई है:-

	लाख रु०
1989-90	152.58
1990-91	169.39
1991-92	232.04

(घ) और (ङ) एन टी सी (एच सी) द्वारा निर्धारित तथा सहायक निगमों के निदेशक बोर्ड द्वारा विविवत अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार छूट दी जाती है । इस प्रकार से दी गई छूट की सहायक निगमों के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के साथ-साथ सांविधिक तथा सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा समय समय पर जांच की जाती है ।

उत्तर प्रदेश में वस्त्र उत्पादकों का निर्यात

2437. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क वापसी की अनुमति और कोटा नीति का सहारा लिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में कितना कार्य किया गया ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में कितने मूल्य की हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुओं का उत्पादन हुआ जिनका निर्यात किया गया और आगामी वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) देश से निर्यात के लिए शुल्क वापसी अनेक वस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं के लिए दी जाती है जिनमें उत्तर प्रदेश में निर्मित तथा वहां से निर्यातित वस्तुयें भी शामिल हैं। इसी प्रकार वार्षिक कोटाओं का अनुकूलतम उपयोग करने तथा निर्यात व्यापार की सुव्यवस्थित उन्नति सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने वस्त्रों और परिधानों के लिए हकदारी वितरण नीति बनाई है। यह नीति उत्तर प्रदेश से किए जा रहे निर्यात सहित देश के सभी भागों से किए जा रहे निर्यात पर समान रूप से लागू होती है ।

(ग) राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात लक्ष्य भी राज्य-वार निर्धारित नहीं किए जाते हैं।